खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). जी नहीं । अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है । भारत सरकार के किसी आदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जिला रामपुर (उ० प्र०) में गोवंश के पशुओं का वध

859. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अपने दौरे के बाद सरकार को एक विस्तृत पत्र लिखा है जिसमें इस जिले में 50,000 गोवंश के पशुओं के वध के बारे में कहा गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इसको रोके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

राजस्थान से भारी संख्या में पशुओं को अन्य स्थानों में ले जाना

860. **श्रीयशपाल सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गम्भीर अकाल की स्थिति के कारण राजस्थान के जेसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिलों से पशुओं के भारी संख्या में अन्य स्थानों में जाने के तथ्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति गम्भीर होने के कारण पशुओं का वध करने के लिये भारी संख्या में पशु उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पशुओं को अपने स्तर पर भेजने का है, ताकि इन पशुओं का वध रोका जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राजस्थान सरकार इन जिलों से या उन राज्य के अन्य जिलों में या उन स्थानों में, जहां कि चारा और पानी उपलब्ध हैं, पशुओं के परिवहन की सुविधाएं, पहले ही प्रदान कर रही हैं, जिससे कि अगली मौनसून मौसिम तक पशुओं को संरक्षित रखा जा सके ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

Employees Provident Fund Organisation

*861. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Law had earlier advised that the Employees Provident Fund Organisation was an industry; and

(b) if so, the reasons for changing their opinion now?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI). (a) Yes. In April, 1966.

(b) The present opinion is based on the recent judgments of the Supreme Court in the case of the Madras Gymkhana Club and the Cricket Club of India, Bombay.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक अशान्ति

*862. **श्री भोलानाथ मास्टर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :